Laid on the table of
Lok Sabha : 16/12/2015
Rajya Sabha : 18/12/2015

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट तथा विधीक्षत खातों की समीक्षा

रेलटेल का सितंबर 2000 में रेल मंत्रालय के अधीन अनुसूची ए कंपनी के रूप में गठन किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिक संचार से संबंधित अवसंरचना मुहैया कराके गाड़ी परिचालन एवं रेल नेटवर्क को आधुनिकीकरण करना है।

2. रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, रेलटेल भारतीय संचार बाजार को सेवाएं मुहैया कराता है। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंडविड्थ आईपी-वीपीएन, एमपीएलएस, एनजीएन आधारित वॉयस केरिज सेवाएं, को-लोकेशन स्पेस, डाटा सेंटर सेवाएं, रेलवायर सेवाएं और टेली प्रेज़ेन्स (टीपास) सेवाएं शामिल हैं।

3. मंत्रालय द्वारा रेलटेल को 15 करोड़ रु. की मूल पूंजी मुहैया कराई गई थी और इक्विटी पूंजी के बदले रेलटेल को इसकी ओएफसी परिसंपत्तियां अंतरित की गई थीं। रेलटेल की मौजूदा प्रदत्त पूंजी 320 करोड़ रु. है और 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की शुद्ध संपत्ति 1004 करोड़ रु. है।

4. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, रेलटेल ने आईपी-एमपीएलएस आधारित डाटा नेटवर्क के अलावा, ऑप्टिकल फाइबर केबल चालू करके और 10जी/2.5 जी क्षमता वाले मल्टीपल नेटवर्क के जरिए विस्तार करके अपने प्रयास जारी रखे हैं। ओएफसी नेटवर्क में लगभग 44,279 आरकेएम तक बढ़ोतरी हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित 600 शहर एवं 4000 टाउन कनेक्ट हुए हैं। अन्य 6500 आरकेएम का निर्माण कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। वर्ष के दौरान, रेलटेल ने गुड़गांव में टियर-III का अपना दूसरा डाटा सेंटर चालू कर दिया है। पिछले वर्ष सिकंदराबाद में चालू किए गए इसी प्रकार के टियर-III डाटा सेंटर के उपलब्ध होने से, रेलटेल अब अपने ग्राहकों को डिज़ास्टर रिकवरी सेवाएं भी मुहैया करा सकता है। को-लोकेशन आवश्यकताओं के अलावा, डाटा सेंटर सुविधा होने से, उद्यमों और सरकारी संगठनों को विभिन्न किस्म की बेहतर सेवाएं मुहैया कराने में सुविधा होगी।

5. रेलटेल ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भी नेशनल नॉलेज नेटवर्कलिंक मुहैया कराई है। मार्च 2015 तक, रेलटेल ने नेटवर्क को परिचालित करने के लिए 26 करोड़ लिंक, 124 डिस्ट्रीब्यूशन लिंक ओर 434 एक्सेस लिंक मुहैया कराए हैं।

6. सार्वजनिक सेवा दायिता निधि योजना (यूएसओएफ) के अंतर्गत संचार विभाग ने एनई-I एवं एनई-II (एनई-I के अंतर्गत मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एनई-II के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड) में ओएफसी बिछाने की परियोजना आबंटित की है। वर्ष के दौरान, रेलटेल ने त्रिपुरा के सभी नोड पूरे कर दिए हैं। मार्च 2015 तक, एनई-I के अंतर्गत, त्रिपुरा में लगभग 480 आरकेएम, मिज़ोरम में 76 आरकेएम, मेघालय में 272 आरकेएम और एनई-II के अंतर्गत नागालैण्ड में 98 आरकेएम एवं अरुणाचल प्रदेश में 106 आरकेएम ओएफसी बिछाए गए हैं।

7. भारत सरकार की ओर से रेलटेल को तीन कार्यान्वयन एजेंसियों में से ब्रॉडबैण्ड पर सभी पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का नाम अब बदलकर भारतनेट कर दिया गया है। रेलटेल को 11 राज्यों में 36000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य आबंटित किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश) तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली शामिल हैं। रेलटेल के लिए इस परियोजना का कुल मूल्य लगभग 2500 करोड़ रु. होगा।

रेलटेल ने इस परियोजना के अंतर्गत, 3074 आरकेएम की डक्ट और 1056 आरकेएम की ओएफसी बिछा दी हैं।

8. वर्ष के दौरान, रेलवे ने रेलटेल को देश में लगभग 400 स्टेशनों में से ए1 व ए कोटि के स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। रेलटेल ने बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नै एवं गोवा में पहले ही वाई-फाई सुविधा चालू कर दी है। बहरहाल, रेलटेल ने सीमित अवधि मॉडल के रूप में किसी एक टेलीफोन ऑपरेटर की सेवाओं का उपयोग करते हुए आगरा, अहमदाबाद, वाराणसी, हावड़ा, सीएसटी/मुंबई एवं सिकंदराबाद में 6 अन्य स्टेशनों पर सुविधा मुहैया कराएगा। इसके अलावा, रेलटेल और डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो) ने राजीव चौक स्टेशन, कश्मीरी गेट स्टेशन, विश्वविद्यालय स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय स्टेशन, हौज़ ख़ास स्टेशन के पांच मेट्रो स्टेशनों में वाई-फाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9. रेलटेल के ग्राहकों में, एयरटेल, टीटीएसएल/टीटीएमएल, एयरसेल, एमटीएस, वोडाफोन, आइडिया आदि जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर, एनआईसी, आर्मी, डीआरडीओ, बीएआरसी, डीडीए आदि जैसे सरकारी संगठनऔर आरबीआई/आईडीआरबीटी, एसबीआई, बैंक आफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, आईसीआईसीआई आदि जैसे बैंक शामिल हैं। रेलवे की पीआरएस, यूटीएस, रेलनेट, नियंत्रण संचार आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को भी रेलटेल के नेटवर्क के जरिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

10. सीवीसी की सिफारिशों के अनुसरण में, इस वर्ष रेलटेल ने इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) अपनाया है और अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलटेल को आईपी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाचडाग के रूप में इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटीग्रिटी पैक्ट के अंतर्गत 15 करोड़ रु. मूल्य से अधिक की सभी निविदाएं कवर होती हैं।

11. पेपर रहित कार्यप्रणाली और पारदर्शिता के महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, रेलटेल ने अखिल भारतीय आधार पर पहले ही अपने सभी विभागों पर ईआरपी को कार्यान्वित कर दिया है। ईआरपी के कार्यान्वयन से रेलटेल को अपनी प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने और अपने परियोजना निष्पादन को सुदृढ़ करने में लाभ मिलेगा। इसके अलावा, ईआरपी के जरिए समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर, समीक्षा के लिए एमआईएस के रूप में संगठन के समग्र प्रबंधन में सुविधा होगी।

12. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए वित्तीय परिणामों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	**2014-15**	**2013-14**
(i) आय	554	538
(ii) परिचालन व्यय	298	284
(iii) सकल लाभ	166	169
(iv) कर उपरांत लाभ	121	138
(v) भुगतान किया गया लाभांश	17	17
(vi) सकल ब्लॉक	1236	1078
(vii) शुद्ध मूल्य	1004	913

*****